बिहार में भूमि विकास बैंकों द्वारा धन-राशियों का उपयोग

1400. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या कृषि मंत्री 7 अगस्त, 1987 को राज्य सभा मे अतारांकित प्रश्न 1422 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंको को दी गई धनराशि का सही-सही उपयोग किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बोरिंग पम्प सेटो की आपूर्ति करने मे किसानो से एक बहुत बड़ी धनराशि वसूल की गई है, और इसमे करोड़ो रुपये की धोखाधडी अंतर्ग्रस्त है , यदि हां, तो क्या "नाबार्ड" ने इस मामले की जांच की है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण विकास विभाग ने उक्त भूमि विकास बैंकों पर लगाये गये आरोपो की जांच की थी और बिहार सरकार को इस संबंध मे कार्यवाही करने के लिये कहा गया था ; यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय मे कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) तथा (ख) विभिन्न एजेसियो से मिली जानकारी के अनुसार अब तक बिहार राज्य भूमि विकास बैंक को दी गई धनराशि का सब मिलाकर सही-सही उपयोग किया गया है । तथापि, बिहार के दो जिलों मे कुछ अनियमितताओ और बिहार राज्य भूमि विकास बैंक के अधिकारियो के भ्रष्टाचार प्रक्रिया मे शामिल होने का तथाकथित आरोप ध्यान मे आया है । यह तथ्य है कि 5 अश्व शक्ति वाले डीजल पम्प सैटो की आपूर्ति करने मे किसानो से बड़ी धनराशि वसूल की गई है । राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने इस मामले की जाच-पडताल की है । जाच पडताल डीलरों, बिहार राज्य भूमि विकास बैंक के अधिकारियों और अन्य एजेसियों का इसमे शामिल होना पाया गया है । धोखाधडी मे अंतर्ग्रस्त सही धनराशि की अभी जानकारी नही है । नाबार्ड ने भी अपनी जाच पडताल की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमे बिहार राज्य भूमि विकास बोर्ड द्वारा पम्प सैटो के ऋणो मे कदाचार का मामला बिहार सरकार के ध्यान मे आया है । इस मामले की छान-बीन करवाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है ।

(ग) बिहार मे बोरिंग उपस्करणों तथा पम्प सैटो की आपूर्ति मे घपला करने के बारे मे मिली शिकायत के आधार पर, ग्रामीण विकास विभाग ने आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को लिखा था । राज्य सरकार ने प्राथमिक जाच करने के बाद कहा कि छोटे किसानो के लिए कुओ मे नल लगाने के कार्यक्रम में धनराशि का दुर्प्रयोग किया गया था, जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से पृथक एक विशेष कार्यक्रम था और राज्य के लघु सिचाई विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई धन-राशि से चलाया गया था । राज्य सरकार ने अपने सतर्कता विभाग को इस मामले पर आगे जाच करने का कार्य सौंपा है । जिसकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है ।

Agreement with IPJMC

1401. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Doordarshan prevented the Pak T.V. from signing an agreement with Indo-Pak Joint Management Committee (IPJMC) on Reliance World Cricket Cup; and

(b) if so, the reasons therefor?